

## विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिएं। -रोबिन शर्मा

## विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के साथ अन्याय कब तक?

एक समय था जब विश्वविद्यालय में शिक्षक बनना केवल नौकरी नहीं, बल्कि सम्मान, प्रतिष्ठा और बौद्धिक गौरव का प्रतीक माना जाता था। राजस्थान सहित पूरे देश में विश्वविद्यालयों की पहचान ज्ञान, शोध और उत्कृष्ट शिक्षण के केंद्रों के रूप में होती थी। विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक समाज के सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित वर्ग में गिने जाते थे। उस दौर में विश्वविद्यालयों के वेतनमान राजकीय महाविद्यालयों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक थे और योग्य शिक्षाविद विश्वविद्यालयों में आने को अपना सौभाग्य मानते थे।

लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जिन विश्वविद्यालयों को कभी राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला कहा जाता था, वे अब सरकारी उपेक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण और वित्तीय भेदभाव के शिकार बन चुके हैं। सबसे अधिक पीड़ा की बात यह है कि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

सत्तर और अस्सी के दशक में विश्वविद्यालयों में उत्कृष्ट विद्वानों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूर्व सेवाओं का समायोजन और सम्मानजनक सेवा शर्तें दी जाती थीं। कई बार तो केवल योग्यता और शोध उपलब्धियों के आधार पर प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को विश्वविद्यालयों में नियुक्त कर लिया जाता था। दूसरी ओर राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों का वेतनमान सामान्य सरकारी अधिकारियों के समान था और उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी केवल 55 वर्ष थी। जबकि विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी। यही कारण था कि महाविद्यालयों के शिक्षक विश्वविद्यालयों में आने के लिए उत्सुक रहते थे।

समय बदला और राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर भी लगातार प्रहार शुरू हो गए। सरकार ने विश्वविद्यालयों को एमओयू के माध्यम से अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया और स्पष्ट संकेत दिया कि निर्देशों की अवहेलना करने पर अनुदान रोका जा सकता है। परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय अब स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थान न रहकर सरकारी विभागों की तरह संचालित होने लगे हैं।

आज विश्वविद्यालयों की हालत चिंताजनक है। शिक्षकों के लगभग 80 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। प्रतिभाशाली युवा अब विश्वविद्यालयों में करियर बनाने से बच रहे हैं। शोध और

अब समय आ गया है कि सरकार विश्वविद्यालय शिक्षकों के साथ हो रहे इस भेदभाव को समाप्त करे, लंबित वित्तीय लाभ तुरंत प्रदान करे, रिक्त पदों को भरे और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करे। अन्यथा इतिहास यह दर्ज करेगा कि जिस राज्य ने कभी शिक्षा और विद्वता की परंपरा पर गर्व किया था, उसी ने अपने विश्वविद्यालयों को धीरे-धीरे कमजोर होने दिया।

से एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का प्रावधान किया गया। यह लाभ राज्य कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालयों के अशैक्षणिक कर्मचारियों को भी दिया गया।

इसके बाद राजकीय महाविद्यालय शिक्षकों ने भी यह लाभ मांगा और सरकार ने 10 मई 2021 को अधिसूचना जारी कर उन्हें यह सुविधा प्रदान कर दी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विश्वविद्यालय शिक्षकों को इस लाभ से वंचित रखा गया।

कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने जब यह मुद्दा उठाया, तब संबंधित विश्वविद्यालयों ने सरकार से अनुमति मांगी। चार वर्षों तक फाइलें घूमती रहीं, आंकड़े जुटाए जाते रहे और अंततः यह तर्क दिया गया कि यदि कृषि विश्वविद्यालय शिक्षकों को यह लाभ दे दिया गया तो अन्य विश्व विद्यालय के शिक्षक भी ऐसी मांग करेंगे और सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। यह तर्क न केवल हास्यास्पद है बल्कि गहरे भेदभाव को भी उजागर करता है। लाखों सरकारी कर्मचारियों और हजारों महाविद्यालय शिक्षकों को यह लाभ देते समय सरकार को वित्तीय भार महसूस नहीं हुआ, लेकिन विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के मामले में अचानक खजाना खाली दिखाई देने लगा। क्या विश्वविद्यालयों के शिक्षक इस राज्य के कर्मचारी नहीं हैं? क्या उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए?

सच्चाई यह है कि सरकार की इस उपेक्षापूर्ण नीति ने विश्वविद्यालयों का मनोबल तोड़ दिया है। योग्य शिक्षक हतोत्साहित हैं, नई प्रतिभाएँ विश्वविद्यालयों में आने से बच रही हैं और शोध तथा अकादमिक गुणवत्ता लगातार गिर रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में विश्वविद्यालय केवल डिग्री बाँटने वाले संस्थान बनकर रह जाएंगे।

राज्य सरकार को समझना होगा कि विश्वविद्यालय केवल भवनों और प्रशासनिक ढाँचों का नाम नहीं है। विश्वविद्यालयों की आत्मा उनके शिक्षक होते हैं। यदि शिक्षकों को सम्मान, समानता और न्याय नहीं मिलेगा तो उच्च शिक्षा व्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती।

अब समय आ गया है कि सरकार विश्वविद्यालय शिक्षकों के साथ हो रहे इस भेदभाव को समाप्त करे, लंबित वित्तीय लाभ तुरंत प्रदान करे, रिक्त पदों को भरे और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करे। अन्यथा इतिहास यह दर्ज करेगा कि जिस राज्य ने कभी शिक्षा और विद्वता की परंपरा पर गर्व किया था, उसी ने अपने विश्वविद्यालयों को धीरे-धीरे कमजोर होने दिया।

-अतिथि सम्पादक,  
डा. पी. सी. कंटालिया  
पूर्व प्रोफेसर एवं मुख्य मूढ वैज्ञानिक  
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, उदयपुर

## गांव की चौपाल से शासन की चौखट तक : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवाद आधारित प्रशासन



राजेन्द्र गहलगत

राजनीति और प्रशासनिक परंपरा में जनसंवाद को हमेशा एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों गाँव-गाँव जाकर ग्राम चौपाल, रात्रि विश्राम, सुबह का भ्रमण और आमजन से प्रत्यक्ष संवाद कर शासन की शैली को नई दिशा दे रहे हैं। यह दौर सत्ता और समाज के बीच उस दूरी को कम करने का सार्थक प्रयास है, जो अक्सर प्रशासनिक ढाँचे में दिखाई देती है।

राजस्थान जैसे विशाल और विविधताओं वाले राज्य में शासन केवल सचिवालयों और बैठकों से संचालित नहीं हो सकता। यहाँ रंगिस्तान की पीढ़ा अलग है, आदिवासी अंचलों की आवश्यकताएँ अलग हैं और सीमावर्ती गाँवों की चुनौतियाँ अलग। ऐसे में मुख्यमंत्री का सीधे गाँवों में पहुँचकर लोगों की बात सुनना लोकात्मक संवेदनशीलता का

परिचायक है।

मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतीय राजनीति में गाँवों के दौरे सामान्य बात हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री का गाँव में रुककर वहाँ की वास्तविक परिस्थितियों को समझने का प्रयास प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब कोई जनप्रतिनिधि गाँव में रात बिताता है तो उसे केवल मंच से दिखाई देने वाला विकास नहीं, बल्कि पानी की समस्या, बिजली की स्थिति, स्कूलों की वास्तविकता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही अनुभव नीतियों को व्यवहारिक बनाता है।

प्रातःकालीन ग्राम भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री का महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना भी इस अभियान की बड़ी विशेषता बनकर उभरा है। सामान्यतः सरकारी कार्यक्रमों में केवल चुनिंदा प्रतिनिधियों या अधिकारियों से संवाद होता है। मुख्यमंत्री सीधे ग्रामीण महिलाओं से पेयजल, गैस, राशन या शिक्षा की जानकारी लेते हैं और इससे प्रशासनिक फाइलों के पीछे छिपी वास्तविकता सामने आती है। इसी प्रकार बच्चों से शिक्षा और युवाओं से रोजगार पर चर्चा शासन की प्राथमिकताओं को मानवीय स्वरूप देती है।

ग्रामीण राजस्थान में आज भी बड़ी संख्या में लोग जिला मुख्यालय या जयपुर तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाते।

ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री का स्वयं गाँव तक पहुँचना एक प्रकार से सरकार आपके द्वार की अवधारणा को व्यवहार में उतारने जैसा है। यह लोकतंत्र की उस भावना को मजबूत करता है जिसमें जनता केवल मतदाता नहीं, बल्कि शासन की सहभागी मानी जाती है।

इन दौरों का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ होने वाली समीक्षा बैठकें हैं। अक्सर विकास योजनाएँ कागजों में सफल दिखाई देती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी गति अपेक्षित नहीं होती। मुख्यमंत्री जब सीधे जिलों में जाकर अधिकारियों से जवाबदेही तय करते हैं, तो प्रशासनिक तंत्र में सक्रियता बढ़ना स्वाभाविक है। इससे योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व संबंधी समस्याओं की वास्तविक स्थिति सामने आती है।

विशेष रूप से यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि इन बैठकों में केवल समीक्षा नहीं, बल्कि समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था में कई बार छोटी समस्याएँ केवल समन्वय के अभाव में वर्षों तक लंबित रहती हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर सीधे हस्तक्षेप से ऐसे मामलों में गति आती है और अधिकारियों में भी जवाबदेही की भावना मजबूत होती है।

राजस्थान जैसे राज्य में जल संकट, ग्रामीण पर्यायन, बेरोजगारी और कृषि आधारित चुनौतियाँ निरंतर बनी रहती हैं और इन परिस्थितियों में शासन का संवेदनशील और सक्रिय होना

अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री के ये दौरे ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं को पुनः केंद्र में लाने का संकेत भी हैं। लंबे समय तक विकास का विमर्श शहरी परियोजनाओं और बड़े निवेशों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा, जबकि राज्य की बड़ी आबादी अब भी गाँवों में निवास करती है। ऐसे में गाँवों की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास प्रशासनिक संतुलन की दिशा में सकारात्मक कदम है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह अभियान महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का जनता के बीच जाना केवल चुनावी समय तक सीमित नहीं होना चाहिए। जनता वह महसूस करना चाहती है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुन रही है और उनके जीवन से जुड़ी चुनौतियों को समझ रही है। मुख्यमंत्री के इन दौरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में यह संदेश देने का प्रयास किया है कि सरकार केवल जयपुर तक सीमित नहीं है।

इन दौरों से प्राप्त अनुभवों को नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में जल संकट प्रमुख समस्या है तो वहाँ दीर्घकालिक जल संरक्षण योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ग्रामीण युवाओं में रोजगार की चिंता अधिक दिखाई देती है तो कौशल विकास और स्थानीय रोजगार आधारित योजनाओं को गति मिल सकती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लिए जाने चाहिए।

-राजेन्द्र गहलगत,  
राज्यसभा सांसद

## उच्च शिक्षा के प्रति सामाजिक उदासीनता - अभिभावकों की खामोशी



अशोक कुमार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा जगत में एक नई सुबह की उम्मीद लेकर आई है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर सामाजिक संगठनों के माध्यम से पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा का क्षेत्र आज एक गहरे संकट से जूझ रहा है। वर्तमान में उच्च शिक्षा की स्थिति स्कूलों की तुलना में कहीं अधिक चिंताजनक है। इसका मुख्य कारण शिक्षा का वह व्यवसायीकरण है जिसने औपचारिक शिक्षण संस्थानों को केवल डिग्री बाँटने वाले केंद्रों में बदल दिया है और कोचिंग सेंटर्स को असली शिक्षा का मंदिर बना दिया है।

डमी स्कूल और कोचिंग संस्कृत: एक समानांतर व्यवस्था आज की सबसे बड़ी विडंबना डमी स्कूल और नॉन-अर्टिडिंग कॉलेज संस्थानों का खोखलापन:

छात्र केवल कागज पर स्कूल या कॉलेज में नामांकित होते हैं, जबकि उनका पूरा समय कोचिंग सेंटर्स में बीताता है। इससे औपचारिक शिक्षण संस्थानों का शैक्षणिक वातावरण पूरी तरह नष्ट हो चुका है।

नैतिकता के अभाव में कोचिंग सेंटर्स: स्कूल और कॉलेज केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार, नैतिकता, खेल और अनुशासन सीखने के केंद्र होते हैं। डमी स्कूल के कारण छात्र इन जीवन-कौशल से वंचित रह जाते हैं और केवल रैंक लाने वाली मशीन बनकर रह जाते हैं।

अभिभावकों की भूमिका और संवादहीनता-उच्च शिक्षा के इस बिगाड़ में अभिभावकों का रवैया भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अभिभावकों की चुप्पी: अक्सर देखा जाता है कि स्कूल तक तो माता-पिता बच्चों को पढ़ाई में संचित लेते हैं, लेकिन कॉलेज स्तर पर पहुँचते ही या तो वे बच्चों की बात नहीं सुनते या अभिभावक बच्चों को कुछ कहना छोड़ देते हैं।

कोचिंग को प्राथमिकता: अभिभावक स्वयं बच्चों को नियमित कॉलेज भेजने के बजाय कोचिंग सेंटर्स की भारी-भरकम फीस भरना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि औपचारिक शिक्षा की डिग्री तो जुगाड़ से भी मिल जाएगी, असली मेहनत तो प्रतियोगी

परीक्षा के लिए करनी है।

विशेष खंड: कोचिंग हब का दबाव और मानसिक स्वास्थ्य का संकट - कोटा और जयपुर जैसे कोचिंग हब आज सफलता की फैक्ट्रियाँ तो बन गए हैं, लेकिन यहाँ से निकलने वाली खबरें दिल दहला देने वाली हैं।

एकाकीपन और असाद: डमी स्कूलों के कारण छात्र अपने हमउम्र साथियों के साथ स्वस्थ सामाजिक वातावरण से कट जाते हैं। कोचिंग की 14-14 घंटे की पढ़ाई और प्रतियोगिताएँ उन्हें एक ऐसे अंधेरे कमरे में धकेल देती हैं जहाँ केवल नंबर मानने रहते हैं।

अभिभावकों की अवास्तविक उम्मीदें: अभिभावक बच्चों को कोचिंग में भेजकर यह मान लेते हैं कि अब उनका चयन निश्चित है। यह उम्मीद बच्चों पर 'प्रदर्शन के दबाव' के रूप में लद जाती है। जब बच्चा इस दबाव को नहीं झेल पाता, तो वह आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाता है।

संवाद का अभाव: घर से दूर हॉस्टलों में रह रहे छात्रों के पास कोई ऐसा मंच नहीं होता जहाँ वे अपना दुख साझा कर सकें। औपचारिक स्कूलों में होने वाली खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ तनाव कम करने का काम करती थीं, जो कोचिंग संस्कृति में पूरी

तरह लुप्त हैं।

औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता और अप्रासंगिकता-यह एक कड़वा सच है कि आज सरकारी और कई निजी विश्वविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता अत्यंत निम्न स्तर पर है।

अपडेटेड पाठ्यक्रम का अभाव: पाठ्यक्रमों का उद्योगों की मांग या प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर से कोई मेल नहीं है। मूल्यांकन पद्धति: कॉलेज की परीक्षाएँ केवल रटने की शक्ति की जाँच करती हैं, जबकि प्रतियोगी परीक्षाएँ तार्किक क्षमता की। यही कारण है कि छात्र औपचारिक कक्षाओं को समय की बर्बादी मानने लगते हैं।

क्रांतिकारी समाधान: अंकों का एकीकरण और पात्रता परीक्षा-इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान एकीकृत मूल्यांकन हो सकता है:— यदि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतिम चयन में स्कूल और कॉलेज के बतलाफाईंग एजाम्स (12वीं या स्नातक) के अंकों को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए, तो छात्र और अभिभावक औपचारिक शिक्षा को गंभीरता से लेंगे। जब बोर्ड परीक्षाओं या स्नातक के अंकों की वेल्यू बढ़ेगी, तो छात्र डमी स्कूल के बजाय वास्तविक कलासंरूप में लौटेंगे। इससे कोचिंग का एकाधिकार खत्म होगा

और छात्रों पर से एक ही परीक्षा में सब कुछ टॉप पर लागू का दबाव कम होगा। सामाजिक संस्थाओं और सरकार की जिम्मेदारी-उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इसे एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा:—

एनजीओ को अभिभावकों के साथ काउंसिलिंग सत्र आयोजित करने चाहिए ताकि वे डमी स्कूल के खतरे और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को समझ सकें। सरकार को उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द करनी चाहिए जो केवल कागजों पर चल रहे हैं। साथ ही, कोचिंग संस्थानों के लिए कड़े रेगुलेशन एक्ट लागू करने चाहिए।

निष्कर्ष-उच्च शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए नि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया होगा। सरकार को नीतियों में बदलाव कर औपचारिक शिक्षा के अंकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में जोड़ना होगा। अभिभावकों को बच्चों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें डमी स्कूल के बजाय सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करना होगा। अंततः, जब औपचारिक शिक्षा का सम्मान बहाल होगा, तभी देश को वास्तव में योग्य, मानसिक रूप से स्वस्थ और चरित्रवान नागरिक मिलेंगे।

-प्रो. अशोक कुमार,  
पूर्व कुलपति कुनापुर,  
गोरखपुर विश्वविद्यालय

## राष्ट्रीय गौरव की पुनःस्थापना का मोदी सरकार का अभियान रंग ला रहा है- नीदरलैंड से लाए गए लीडेन प्लेट्स



बाचराम बधेल

राष्ट्र का अर्थ है, साझा इतिहास, साझा संस्कृति और साझा विश्वास-साझा उम्मीदों-सपनों में आम नागरिक की भागीदारी। कई विद्वानों ने बार-बार कहा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिन्दू है, चाहे उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो क्योंकि हमारा इतिहास, संस्कृति और पूर्वज साझा हैं। राष्ट्रवाद की इसी बुनियाद को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार मजबूत किया है। चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मसला हो या पूर्व में देश के मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों से लूट कर विदेश ले जाई गई कलाकृतियों, पाण्डुलिपियों व मूर्तियों को वापस लाने का मुद्दा हो, हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा किया है।

पीएम नरेन्द्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान गत 16 मई को नीदरलैंड के पीएम रॉब जैटन की उपस्थिति में 11वीं सदी की

चोलकालीन कॉपर प्लैट्स भारत को सौंपी गईं। यूरोप में लीडेन प्लेट्स और भारत में अनाइमंगलम तापत्रय के नाम से मशहूर ये प्राचीन अभिलेख, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति के महत्वपूर्ण जीवित साक्ष्य हैं। अब तक ये लीडेन शहर स्थित एशियाई लाइब्रेरी ऑफ लीडेन यूनिवर्सिटी में रखे हुए थे। ये 30 किलोग्राम वजन की 21 बड़ी और 3 छोटी प्लैट्स का कलेक्शन है जिसमें चोल शासक राजराजा प्रथम द्वारा नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार के रोजमर्रा खर्च के लिए समीप के गाँव आनाईमंगलम ग्राम व इसके आसपास के क्षेत्र के भू-राजस्व की आय विहार को देने के शाही फरमान के साथ ही राजराज प्रथम के उत्तराधिकारी राजेन्द्र चोल प्रथम द्वारा इस फरमान की पुष्टि का शाही फरमान शामिल है।

यह विहार श्रीविजय साम्राज्य के शासक मारविजयतुंग वर्मन ने 1006 ई. में निर्मित कलाकृति था। श्रीविजय साम्राज्य आज के इंडोनेशिया के सुमात्रा में केन्द्रित था। चोल शासक शैव थे और बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति और उसके खर्च के लिए धन की व्यवस्था उस काल में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता के भारतीय भावना को उजागर करती है।

इन 21 तांबे की प्लेटों को शाही चोल मुहर वाली एक विशाल कांस्य (ब्रॉन्ज़) की अंगुठी से बांधा गया है, जिस पर चोल साम्राज्य का प्रतीक नाथ अंकित है। इनमें तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं का उपयोग किया गया है। 1690 ई. के दशक में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय नागापट्टनम में रहने वाले फ्लोरेंटियस कैपर नाम का डच अधिकारी इन्हें भारत से बाहर ले गया, जिसके बाद से ये नीदरलैंड में रखे हुए थे। 26 मई, 2014 को नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही देश में राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव की नई भावना का दौर शुरू हुआ। विदेशी हमलावरों द्वारा शासक राजराज प्रथम से स्थापित रूप से लूटी, कब्जाई गई और चोरी गई प्राचीन कलाकृतियों को वापस लाकर उन्हें मंदिरों, विहारों, पुस्तकालयों में पुनः स्थापित करने का महत्वपूर्ण अभियान शुरू हुआ है। केवल अतीत की वस्तुएँ ही नहीं हैं बल्कि भारत की विरासत और सभ्यता की एक अनमोल कहानी बयां करती हैं। इनकी घर-बापसी सभी देशवासियों के लिए वापसात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। पुरातन वस्तुएं मात्र कलात्मक वस्तुएँ नहीं हैं बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, ऐतिहासिक निरंतरता और सभ्यतागत स्मृति की प्रतीक हैं।

इससे पूर्व नेशनल म्यूजियम ऑफ पुराणियन आर्ट, वाराणसी से तीन ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियों को वापसी बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इनमें लगभग 990 ईस्वी की चोल काल की शिव नटराज प्रतिमा, 12वीं शताब्दी की सोमस्कंद (शिव और उमा) प्रतिमा और 16वीं शताब्दी की विजयनगर काल की संत सुंदरार और परवई की

प्रतिमा शामिल है। ये प्रतिमाएँ 20वीं शताब्दी के मध्य में अवैध रूप से भारत से विदेशों में ले जाई गईं। शिव नटराज मूर्ति मूल रूप से यह तंजावूर जिले के श्री भाव्य औपदेश्वर मंदिर, संत सुंदरार और परवई प्रतिमा तमिलनाडु के वीरसोलपुरम गाँव में स्थित शिव मंदिर व सोमस्कंद प्रतिमा तमिलनाडु के अलापुर गाँव में विश्वनाथ मंदिर से सम्बंधित हैं।

2014 से लेकर अब तक, संस्कृति मंत्रालय, एएसआई, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और प्रवर्तन एजेंसियों के नेतृत्व में निरंतर राजनयिक, कानूनी और संस्थागत प्रयासों के माध्यम से भारत ने गत 12 मई तक विभिन्न देशों से 666 प्राचीन वस्तुओं को सफलतापूर्वक वापस मंगवाया है, जिनमें से 653 वस्तुएँ 2014 के बाद वापस लाई गई हैं। हाल ही में, भारतीय मूल की 657 कलाकृतियों अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय दूतावास को सौंपी गई हैं और एएसआई के विशेषज्ञों द्वारा उनके परिवहन और सत्यापन के लिए व्यवस्थाएँ चल रही हैं।

जुलाई, 2014 में 11वीं शताब्दी की चोलकालीन श्री पुरांतन नटराज की कांस्य प्रतिमा, नवंबर, 2014 में अमेरिका से 61 विभिन्न प्राचीन कलाकृतियों, सितंबर, 2015 अमेरिका से 19 प्राचीन कलाकृतियों जिनमें चोलकालीन कांस्य तथा प्रस्तर प्रतिमाएँ और उनके अवशेष, जनवरी, 2016 में अमेरिका से देवी नामक

चोलकालीन कांस्य प्रतिमा लायी गई। नवंबर, 2016 में अमेरिका से 111, अप्रैल 2017 में सिंगापुर से 10 कलाकृतियाँ जिसमें मूर्तियाँ और पाण्डुलिपियाँ भी शामिल हैं, वापस आईं। जुलाई 2019 में अमेरिका से 67 पुरातन कलाकृतियाँ जिनमें कांस्य प्रतिमा, मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, जनवरी, 2020 में आस्ट्रेलिया से 17, अक्टूबर, 2020 में अमेरिका से 157, दिसंबर, 2021 में अमेरिका से 23, जुलाई 2022 में अमेरिका से 70, मार्च, 2023 में नीदरलैंड से 16, जुलाई, 2023 में अमेरिका से 50, जनवरी, 2024 में अमेरिका से 12 कलाकृतियाँ लाई जा चुकी हैं।

इसके साथ ही भारत सरकार ब्रिटेन के साथ राशनयिक माध्यमों से कोहिनूर की वापसी का प्रयास कर रही है लेकिन ब्रिटिश सरकार और अदालतों का यह स्पष्ट मानना है कि 1849 में लाहौर की संधि के तहत महाराजा दलीप सिंह ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, इसलिए यह एक वैध उपहार या अधिग्रहण था जबकि अन्य अधिकतर मामलों में पुरातात्विक महत्व की कलाकृतियों को लूटा या चोरी किया गया था। ब्रिटेन का रॉयल कलेक्शन कानून इन वैश्वीकृत वस्तुओं को स्थानीय रूप से देश से बाहर भेजने या वापस करने की अनुमति नहीं देते फिर भी कोहिनूर को भारत लौटाने के लिए सरकारी स्तर पर सभी प्रयास जारी हैं।

-बाचराम बधेल,  
भाजपा कार्यकर्ता धौलपुर

### राशिफल गुरुवार 28 मई, 2026

प्रथम ज्येष्ठ मास (अधिक), शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत् 2083, चित्रा नक्षत्र प्रातः 8:08 तक, वारियान योग रात्रि 3:55 तक, बालव करण प्रातः 7:57 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-तुला, मंगल-मेष, बुध-वृष, गुरु-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज प्रदोष व्रत, ईद-उल-जुहा (बकरीद) मु. है।

श्रेष्ठ चौघण्टिया: शुभ सूर्योदय से 7:19 तक, च. 10:42 से 12:24 तक, लाभ अमृत 12:24 से 3:47 तक, शुभ 5:28 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:38, सूर्यास्त 7:10

**मेष** परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

**वृष** व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

**मिथुन** व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कर्क** व्यावसायिक एवं नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

**सिंह** व्यावसायिक कार्यों में प्रगति रहेगी। व्यावसायिक सफलता से मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

**कन्या** आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

**तुला** मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

**धनु** आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संचालित धन प्रातः होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक बर्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

**मकर** व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्र/सुगमता से बने लगे। परिवार में सुख-सुविधाएँ बढ़ेंगी।

**कुंभ** नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संपन्न है। व्यावसायिक बर्ता सफल रहेगी।

**मीन** चन्द्रमा अग्रम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यस्तता हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बर्तने कार्य विवाद सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।